पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की विविध अपील सं.382

=====

सरदार मंजीत सिंह उर्फ मंजीत कपूर पुत्र सरदार संत सिंह मनौरानी रोड, हनुमान मंदिर के पास, संकट मोचन कॉलोनी, वार्ड नं. 7, थाना-मधुबानी, जिला-मधुबानी

अपीलार्थी/गण

बनाम

बौती चतुर्वेदी @ब्यूटी कपूर सरदार मंजीत सिंह की पत्नी @मंजीत कपूर स्वर्गीय कविंद्र चतुर्वेदी की बेटी, हाउस नं. 88, गुरुहट्टा, बक्षी मोहल्ला, संजय प्रिंटिंग प्रेस के पास, रानीपुर, थाना- खजेकला, पटना सिटी, जिला-पटना

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

- वैवाहिक - हिंदी विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत तलाक की कार्यवाही। एकपक्षीय सुनवाई - पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी पत्नी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही में गलती की - नोटिस की संतोषजनक तामील का कोई उल्लेख नहीं।

- समन जारी करना और तामील करना - आदेश-5 - नियम 9,17,19, 20(i) - प्रतिस्थापित तामील का निर्देश देने से पहले - संहिता के आदेश 5 के नियम 9 और 19 का पालन करना होगा

- प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया - विवाह को रद्द करने या तलाक की कार्यवाही के लिए वैवाहिक विवाद गंभीर मामला है - न्यायालय को नोटिस जारी करने के अनुपालन के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। निर्णय को रद्द किया गया - मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजा गया।

यल्लावा बनाम शांतव्वा (1997) 11 एससीसी 159 पर भरोसा किया

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की विविध अपील सं.382

=====

सरदार मंजीत सिंह उर्फ मंजीत कपूर पुत्र सरदार संत सिंह मनौरानी रोड, हनुमान मंदिर के पास, संकट मोचन कॉलोनी, वार्ड नं. 7, थाना-मधुबानी, जिला-मधुबानी

अपीलार्थी/गण

बनाम

बौती चतुर्वेदी @ब्यूटी कपूर सरदार मंजीत सिंह की पत्नी @मंजीत कपूर स्वर्गीय कविंद्र चतुर्वेदी की बेटी, हाउस नं. 88, गुरहट्टा, बक्षी मोहल्ला, संजय प्रिंटिंग प्रेस के पास, रानीपुर, थाना- खजेकला, पटना सिटी, जिला-पटना

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण के लिए : श्रीमति सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : कोई नहीं

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंत्री और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

कैव निर्णय

(द्वारा : माननीय श्री जस्टिस अलोक कुमार पांडे)

तिथी 15-03-2024

वर्तमान अपील 2019 के वैवाहिक मामला संख्या 102 (2019 का सी. एफ. संख्या 102) में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबानी द्वारा पारित दिनांक

20.02.2021 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा और जिसके तहत अपीलकर्ता-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के तहत प्रतिवादी-पत्नी के साथ अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी के मामले का तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी का विवाह दिनांक 31.07.2015 के के-1319 सेक्टर 9 विजय नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) के आर्य समाज मंदिर में किया गया था। इसके बाद विवाह पंजीयक (हिंदू विवाह), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के समक्ष पंजीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने 12.06.17 को बिहार के मधुबानी में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोह के अनुसार शादी की और उसके बाद प्रत्यर्थी-पत्नी अपने माता-पिता के घर (माईक) लौट आईं। याचिका में आगे कहा गया है कि शादी पूरी नहीं हुई थी। यह भी कहा जाता है कि दोनों पक्ष आम/उभयनिष्ठ जगह पर रहते थे, यथा कि मंगौरानी रोड, हनुमान मंदिर के पास, संकट मोचन कॉलोनी, वार्ड संख्या 7, थाना मधुबानी, जिला मधुबानी, बिहार, जो अपीलार्थी के पिता का घर है। समान स्थान पर रहने के दौरान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी-पत्नी ने कभी भी सह-निवास नहीं किया या अपीलार्थी के साथ कभी भी यौन संबंध स्थापित नहीं किए, किसी न किसी बहाने से। याचिका में आगे यह कहा गया है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया गया था जिससे विवाह पूरा नहीं हुआ है। यह आगे दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी-पत्नी का इलाज बोरिंग रोड, पटना स्थित ज्योति पुंज अस्पताल में शुरू हुआ और अंत में स्त्री रोग विशेषज्ञ ने विभिन्न परीक्षाओं और चिकित्सा परीक्षणों के बाद अपीलार्थी-पति को सूचित किया कि प्रत्यर्थी-पत्नी ब्लाइंड वजाइना से पीड़ित थी और वह यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकी। अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह दावा किया जाता है कि उक्त प्रश्न प्रत्यर्थी से पूछा गया था और उसने स्वीकार किया

कि वह शारीरिक और चिकित्सा तथ्य से अवगत थी कि वह पति के साथ सामान्य शारीरिक और यौन संबंध रखने में सक्षम नहीं थी और उसने उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को छुपाया। याचिका में आगे यह कहा गया है कि 16.04.2018 को, अपीलार्थी को प्रतिवादी के अंधी योनि होने के बारे में पता चला और वह यौन संबंध स्थापित करने की स्थिति में नहीं थी और चूंकि 16.04.2018 दोनों पक्ष एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग रह रहे हैं और महिला यौन अक्षमता (एफ.एस.डी.) के आधार पर प्रतिवादी के साथ अपीलार्थी के विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए प्रार्थना की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है लेकिन प्रतिवादी-पत्नी परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और 06.01.2020 को प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ *एकतरफा* सुनवाई के लिए मामला तय किया गया था। विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि याचिका में एक विशिष्ट कथन है कि प्रतिवादी के एफ. एस. डी. के कारण, विवाह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने विशेष रूप से उक्त आधार पर कोई विवाद नहीं किया है। इसलिए, दिनांकित 20.02.2021 का निर्णय इस तथ्य के आलोक में मान्य और टिकाऊ नहीं है कि 2021 का परिवार न्यायालय अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा है जिसका याचिका में किए गए कथन से कोई संबंध नहीं है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिका के पैरा-17 और 18 में विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि अंधी योनि के कारण दोनों पक्ष एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं और उक्त तथ्य अपीलार्थी की जानकारी में 16.04.2018 से पहले नहीं था और अपीलार्थी द्वारा यह भी विशेष रूप से कहा गया है कि उन्हें उक्त तथ्य के बारे में एक महिला डॉक्टर की चिकित्सा जांच के आधार पर पता चला और उक्त तथ्य को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबानी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है और विवादित निर्णय याचिका में बताए गए तथ्यों की सराहना किए बिना पारित किया गया है।

4. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबानी ने अपीलार्थी की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की है। इनमें अपीलार्थी-1 सरदार मंजीत सिंह उर्फ मंजीत कपूर (स्वयं अपीलार्थी), अपीलार्थी-2 सरदार संत सिंह और अपीलार्थी-3 मदनलाल खंडेलबल शामिल हैं।

5. अभिलेख के अवलोकन से हम संतुष्ट हैं कि प्रत्यर्थी-पत्नी को नोटिस की सेवा न देने के आधार पर *एकतरफा* निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है और उसी को पुनः परीक्षण के लिए रिमांड की आवश्यकता है, हम अपीलार्थी द्वारा अपनी याचिका में किए गए कथन के विवरण में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उस आधार की गई कोई भी टिप्पणी पर अवलोकन किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है जब मामले को निचली अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर फिर से चलाया जाता है।

6. यह जाँचने के उद्देश्यों के लिए कि क्या विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा *एकतरफा* निर्णय सही ढंग से पारित किया गया था, हमने परिवार न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और जिससे यह आकलन किया जा सकता है कि मुकदमा 22.04.2019 को दायर किया गया था। 04.05.2019 को परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और 15.05.2019 को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, यदि नोटिस के संबंध में आवश्यकताएं उपलब्ध हैं। 25.07.2019 को पीठासीन अधिकारी वर्तमान कर्तव्य पर थे और 14.08.2019 को अपीलार्थी की ओर से समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए आवेदन दायर किया गया था और अपीलार्थी की ओर से प्रकाशन के लिए 02.09.2019 प्रारूप में प्रस्तुत किया गया था। 23.09.2019 को पेपर का कटिंग प्रकाशन प्रस्तुत किया गया था। 06.01.2020 को प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ *एकतरफा* सुनवाई के लिए मामला तय किया गया था।

7. समन की तामीला के संबंध में परिवार न्यायालय की विभिन्न तिथियों के आदेश पत्र से संकेत मिलता है कि कैसे लापरवाही से और नियमित तरीके से आदेश पारित किया गया है और 04.05.2019 को इस बात की चर्चा नहीं है कि अदालत ने

प्रतिवादी को दिए गए नोटिस की तामील से संतुष्ट है। दिनांकित 04.05.2019 का पहला आदेश पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नोटिस प्रत्यर्थी-पत्नी को तामील हुई और 04.05.2019 से लेकर दिनांक 06.01.2020 के अंतिम आदेश पत्र तक, जिस मामले पर *एक्टरफा* सुनवाई के लिए मामला तय किया गया था, कोई चर्चा नहीं थी कि क्या नोटिस की तामील प्रतिवादी-पत्नी को संतोषजनक रूप से दी गई है या नहीं और परिवार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि प्रकाशन का प्रारूप आवश्यक है और आदेश पत्र से ही यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकाशन कैसे किया गया है। यहां तक कि दिनांक 14.08.2019 के क्रम में भी उस समाचार पत्र का नाम सामने नहीं आ रहा है जिसमें नोटिस प्रकाशित किया जाना था।

8. इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) समन जारी करने और तामील के लिए प्रावधान करता है। नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर रहता है जिसमें मुकदमा दायर किया गया है, या उस अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वाला कोई एजेंट है जिसे समन की तामील स्वीकार करने का अधिकार है, तो समन, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं देता है, या तो उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से किसी एक द्वारा या ऐसी कूरियर सेवाओं के लिए भेजा जाएगा जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं। नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत, समन की तामील प्रतिवादी या उसके एजेंट को संबोधित पंजीकृत डाक पावती द्वारा उसकी एक प्रति वितरित या प्रेषित करके की जा सकती हैं, जो सेवा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कूरियर सेवाओं द्वारा स्वीकार करें जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं।

9. संहिता के आदेश 5 का नियम 17 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जब प्रतिवादी सेवा स्वीकार करने से इनकार करता है, या पाया नहीं जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी नहीं पाया जाता है, तो सेवारत अधिकारी समन की एक

प्रति बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाएगा जिसमें प्रतिवादी सामान्य रूप से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और फिर मूल को उस अदालत को वापस कर देगा जहां से यह जारी किया गया था, उस पर समर्थित या संलग्न एक रिपोर्ट के साथ जिसमें कहा गया है कि उसने इस तरह से प्रति चिपकाई है, जिन परिस्थितियों के तहत उसने ऐसा किया था, और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी। संहिता के आदेश 5 के नियम 19 के तहत, सेवारत अधिकारी की जांच आवश्यक है जहां नियम 17 के तहत समन वापस किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

10. सेवारत अधिकारी की जाँच के बाद संतुष्ट होने पर कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, न्यायालय न्यायालय में किसी विशिष्ट स्थान पर और घर के किसी विशिष्ट हिस्से (यदि कोई हो) पर भी, जिसमें प्रतिवादी 2021 का पटना उच्च न्यायालय एम. ए. No.382 है, चिपकाकर सेवा का निर्देश देने के लिए नियम 20 (1) का आह्वान करने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसे अंतिम बार रहने या व्यवसाय करने के लिए जाना जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया है, या इस तरह से अन्य तरीके से जो अदालत उचित समझती है। इस प्रकार, प्रतिस्थापित सेवा को निर्देशित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले संहिता के आदेश 5 के नियम 9 और 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावा, संहिता के नियम 20 (1-ए) में प्रावधान है कि जहां उप-नियम (1) के तहत कार्य करने वाला न्यायालय किसी समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा सेवा का आदेश देता है, तो समाचार पत्र उस इलाके में प्रसारित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र होगा जिसमें प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

11. वर्तमान मामले में, हालांकि प्रतिवादी-पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश

है, लेकिन नोटिस की सेवा के बिंदु पर, अदालत ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है कि क्या प्रतिवादी-पत्नी को नोटिस ठीक से दिया गया था या नहीं और तुरंत बाद अदालत सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान मामले में प्रकाशन की आवश्यकता थी, हालांकि उक्त आदेश में समाचार पत्र का नाम प्रकट नहीं किया गया है।

12. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, (1997) 11 एस. सी. सी. 159 में रिपोर्ट किए गए **यल्लावा बनाम शांतव्वा** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उद्धृत करना आवश्यक है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निचली अदालत के पास लगभग स्वचालित रूप से संहिता के आदेश 5 नियम 12,15 और 17 द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्रत्यर्थी की सेवा के लिए कदम उठाए बिना प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन प्रदान नहीं हो सकता था यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिस्थापित सेवा का अंतिम उपाय के रूप में सहारा लिया जाना चाहिए जब प्रतिवादी को सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती है और अदालत संतुष्ट है कि यह मानने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, या कि किसी अन्य कारण से समन सामान्य तरीके से नहीं दिया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग स्वतः ही प्रतिस्थापित सेवा की प्रक्रिया का सहारा लिया गया था। तत्काल मामले में भी, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, विद्वत निचली अदालत ने संहिता के आदेश 5 नियम 20 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तों के बारे में संतुष्टि दर्ज किए बिना लगभग तुरंत प्रार्थना की अनुमति दे दी है।

13. वर्तमान मामले में, परिवार न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने लापरवाही और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है। दिनांकित 06.01.2020 के आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उचित सहारा लिए बिना मामले को *एकतरफा* सुनवाई के लिए तय किया गया है। यह मामला जो विवाह को रद्द करने या तलाक की कार्यवाही से

संबंधित वैवाहिक विवाद से संबंधित है, एक गंभीर मामला है और यह पूरे जीवन को जोड़ता है जो पति और पत्नी के खिलाफ जिनके खिलाफ निरर्थकता या तलाक की घोषणा के लिए डिक्री मांगी गई है। उक्त मामले में, अदालत को नोटिस जारी करने के अनुपालन के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि अदालत को सभी वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए जो पक्ष की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के संबंध में संहिता के आदेश 5 नियम 12,15,17 और 20 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तों के बारे में अपेक्षित है। इसके अलावा, परिवार न्यायालय ने फैसला पारित करते समय पक्षकार के तर्क को निर्दिष्ट नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श-1) के लेखक की भी जांच नहीं की गई है। उपरोक्त मामले पर निर्णय लेने के लिए, उस विवाद पर निष्कर्ष देना आवश्यक है जो वर्तमान अपील का आधार है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि प्रत्यर्थी-पत्नी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया था और प्रतिस्थापित सेवा को दूषित करने के निर्देश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, इसलिए, प्रत्यर्थी-पत्नी के खिलाफ पारित एकतरफा निर्णय को दरकिनार किया जाना चाहिए। तदनुसार, 2019 के वैवाहिक मामला संख्या 102 (2019 का सी. एफ. संख्या 102) में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबानी द्वारा पारित दिनांक 20.02.2021 का फैसला दरकिनार किया जाता है। इस मामले को अपने गुण दोष के आधार पर विधिनुसार निष्पादन हेतु कुटुंब न्यायालय को वापस भेजा जाता है- संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद, इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

15. निचली अदालत के अभिलेख को तुरंत विद्वत निचली अदालत में वापस भेजा जाए।

(पी. बी. बजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।